LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
RNI NO. 45823/86 REGISTERED NO. FARIDABAD/46/2020-22; DL(ND)-11/6042/2018-20; U(C)-31/2018-20

OC

और भी मर्ज हैं कोविड के सिवा | कोविड के नए उपचार | धारावी: बम पर बैठा मुंबई | उद्योग फिर से कैसे शुरू हों

इंडिया टुडे

6 मई, 2020 40 रुपए

उम्मीदों की फसल

रबी की जोरदार फसल पर है 20 करोड़ किसानों, चार फीसद जीडीपी और आर्थिक बहाली का दारोमदार

पंजाब के मोहाली जिले में रुरका गांव के किसान जत्थेदार तारा सिंह गरेवाल

www.indiatodayhindi.in

Scanned by CamScanner

PODDAR GROUP OF INSTITUTIONS

Since 1998

PODDAR INTERNATIONAL COLLEGE
Affiliated to University of Rajasthan, Approved by UGC

PODDAR MANAGEMENT & TECHNICAL CAMPUS
Affiliated to Rajasthan Technical University, Approved by AICTE

BEST PRIVATE COLLEGE in RAJASTHAN 2019

STATE LEVEL AWARD in Co-education Category for NSS

INDIA TODAY 2nd RANK in Rajasthan

BUSINESS TODAY TOP 10 RANK, B-School, Rajasthan

ToI 3rd RANK in Rajasthan 2017

Excellent Management College in Rajasthan

Education Excellence Awards ASSOCHAM

GERA Excellence Awards 2019

NAAC ACCREDITED

SCIENCE	COMMERCE & MANAGEMENT	ARTS, IT & JMC	DESIGN
•B.Sc.(Maths, Bio) - 3 Yrs.	•B.Com. - 3 Yrs.	•BA, BCA - 3Yrs.	•B.Des.-4 Yrs. (Fashion/Interior)
•M.Sc.(Chem, Zoology, Maths Botany, Physics) - 2 Yrs.	•BBA - 3 Yrs.	•B.Voc. (JMC) - 3Yrs.	•B.Voc.-3 Yrs. (Fashion/Interior)
•Ph.D. (Zoology, Chemistry)	•M.Com. - 2 Yrs.	•MA, M.Sc. (IT) - 2 Yr.	•M.Voc.-2 Yrs.(Fashion/Interior)
	•MBA - 2 Yrs.	•Diploma (JMC) - 1Yr.	•Diploma - 1Yr. / 2 Yrs.

DIPLOMA & CERTIFICATE
• D.Pharm (2 Yrs.) • DMLT, DMRT • Certificate in Accounting Technician (CA) • Homeopathic Dispensing • Community Health (Jan Swasthya) • Ayurveda Therapy

GOVT. JOBS | BANK | RAILWAY | SSC | DEFENCE | UPSC

- 21 Years of Academic Excellence
- Real life Business case studies based program
- Frequent industry visits
- Foreign Universities Collaboration & Exchange Program
- Value Added Certification Courses
- 100% Placement Assistance
- Paid Summer Internships
- On the job training
- Free Competitive Classes for UPSC, SSC, Railway, Bank etc.

OUR PROMINENT RECRUITERS

Sector-7, Nr. Shipra Path, Mansarovar, Jaipur

9414073127, 9116674491
0141-2781232

admission@poddarinstitute.org
www.poddarinstitute.org

Scanned by CamScanner

प्रधान संपादक की कलम से

धरती के हाल के इतिहास में ऐसे वक्त की कल्पना भी मुश्किल है. दुनिया भर में नॉवेल कोरोना वायरस महामारी अब तक 1,90,000 लोगों की जान ले चुकी है और करीब 27 लाख लोगों को संक्रमण का शिकार बना चुकी है. उसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक लॉकडाउन हो चुका है. फैक्टरियां बंद हैं, हवाई जहाज जमीन पकड़े हुए हैं और सरहदें सील की जा चुकी हैं. तेल की कीमतें गोता लगा चुकी हैं, खासकर अमेरिका में तो तेल उत्पादक वितरकों से अतिरिक्त तेल लेने के लिए पैसे देने की पेशकश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है. यह 'महा लॉकडाउन' मंदी है, जैसा कि आइएमएफ ने कहा है और इस दौरान विकसित देश करीब 6 फीसद की नकारात्मक वृद्धि दर पर पहुंच जा सकते हैं जबकि भारत मामूली-सी वृद्धि या उससे भी बदतर हालत में जा सकता है. यह दुनिया में 1930 के दशक की महामंदी से भी बुरा दौर हो सकता है. फिर, बदतर यह कि विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के इस महीने के आकलन के मुताबिक, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 2020 के अंत तक 26.5 करोड़ लोग भुखमरी झेल सकते हैं. यह सब 21वीं सदी में होना वाकई भयावह त्रासदी और पूरी दुनिया के लिए शर्मनाक होगी, जब टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी पूरी तरह हमारे काबू में है.

14 फरवरी, 2018 का आवरण

भारत में कोविड-19 से अभी तक 686 जानें ही गई हैं लेकिन 40 दिनों के लॉकडाउन के बावजूद हम वायरस पर काबू पाने के लिए जूझ रहे हैं. टेस्ट की दर बढ़कर प्रति दस लाख 367 हो गई है लेकिन यह अब भी अफसोसनाक ढंग से नाकाफी और दुनिया में सबसे कम है. हमें समस्या को ही ठीक से जानने के लिए ही लंबी दूरी तय करनी है. लॉकडाउन से हमें इस महामारी के लिए स्वास्थ्य ढांचा तैयार करने की मोहलत मिली है. हालांकि, दूसरी तरफ, हर हफ्ते अर्थव्यवस्था को 2 लाख करोड़ रु. की चपत लग रही है और गरीब गहरी गरीबी में धंसते जा रहे हैं. अर्थव्यवस्था के तीन बड़े इंजनों में दो—सेवा और उत्पादन क्षेत्र—बंद पड़े हैं. इन दोनों की जीडीपी में हिस्सेदारी 70.6 फीसद और इनमें कुल श्रम बल का 43.9 फीसद रोजगार पाता है. यह बीमारी देश के आर्थिक रूप से अहम शहरी क्षेत्रों पर भारी मार कर रही है, जिसमें 35 फीसद खासकर राज्यों की राजधानियों की देश की जीडीपी में 20 फीसद हिस्सेदारी है.

खुशकिस्मती से हमारी अर्थव्यवस्था का तीसरा इंजन कृषि में कुछ उम्मीद दिख रही है. खेती-बाड़ी में देश का लगभग आधा श्रम बल लगता है लेकिन जीडीपी में इसकी 17 फीसद की सबसे छोटी हिस्सेदारी है. इसकी वृद्धि दर भी मामूली 2.8 फीसद सालाना है. इस साल जाड़ा कुछ लंबा खिंचा और अनुकूल बारिश हुई तो गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड 10.6 करोड़ टन होने वाली है. सरकार के गोदाम 3 करोड़ अनाज से भरे पड़े हैं जो साल भर के लिए काफी है. भारत गेहूं, चावल, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है. दूध और दलहन का तो सबसे बड़ा उत्पादक है. देश बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. यही वजह है कि हम डब्ल्यूएफपी की भुखमरी की आशंका वाले देशों की सूची में नहीं हैं.

खुशी की बात यह है कि इस साल की पैदावार पिछले साल के मुकाबले कम से कम 6 फीसद ज्यादा होगी. इस पैदावार—गेहूं, चना, दालें और सरसों—का बड़ा हिस्सा उत्तरी और पश्चिमी राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है. इस मुश्किल वक्त में इस साल की फसल वरदान जैसी है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में 8 लाख करोड़ रु. या जीडीपी का 4 फीसद आ जाने की उम्मीद है. इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, और उम्मीद है, खस्ताहाल अर्थव्यवस्था में जान लौटेगी.

सरकार इससे वाकिफ है. उसने 24 मार्च को 15,841 करोड़ रु. जारी किए, ताकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सालाना 6,000 रु. की राशि की पहली किस्त 2000 रु. दिए जा सकें. इसका लक्ष्य 12 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना है. मनरेगा के तहत रोजाना का पारिश्रमिक 182 रु. से बढ़ाकर 202 रु. कर दिया गया है. इस योजना के तहत अधिकतर काम कृषि क्षेत्र के हैं, यह योजना अपने पूरे स्वरूप में चले तो 13 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया करा सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल को मजदूरों की समस्या से जूझ रहे किसानों की मदद के लिए उच्चस्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई. गृह मंत्रालय ने 20 अप्रैल को फसल की कटाई के लिए मजदूरों और कृषि उपकरणों की जिलों के बीच आवाजाही को मंजूरी दे दी. पंजाब और बिहार जैसे राज्य भी अपने स्तर पर फसल की कटाई सहज बनाने के उपाय कर रहे हैं. सरकारें इस संकट में किसानों और उपज का डेटा भी तैयार कर रही हैं. बिहार सरकार पंचायत स्तर पर खरीद और खरीफ के बीज मुहैया कराने की योजना बना रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रकों के लिए भी उबर और ओला जैसे एग्रीगेटर ऐप बनाने का विचार सामने रखा है, ताकि ट्रकों की तलाश सहज हो सके.

हमारी आवरण कथा 'उम्मीदों की फसल' मौजूदा मायूसी के दौर में कुछ खुशी की वजह है. कंसल्टिंग एडिटर अजीत कुमार झा, सीनियर एडिटर अनिलेश एस. महाजन और देश भर के हमारे ब्यूरो ने इस साल के बंपर फसल की वजहों को तलाशा और यह भी कि क्यों यह इस दुर्दिन में राहत बन सकती है.

आज सरकार फसल को बचाने के लिए नए तरीके तलाश रही है तो संभव है वह सत्ता में आने के बाद पहली दफा कृषि पर अधिक ध्यान दे. इस संकट में कुछ स्वागतयोग्य बदलाव भी आ रहा है. अब कृषि गतिविधि और ई-नैम के जरिए मार्केटिंग के डिजिटलीकरण पर जोर बढ़ सकता है. अगर सरकार कोरोना के बाद के दौर में इस ओर रुख करती है तो इससे कृषि की उत्पादकता में भारी वृद्धि होगी. इस बीच, आइए अपनी तन्हाई में हम अर्थव्यवस्था के खुलने का जश्न मनाएं. सुरक्षित रहें, हौसला और उम्मीद रखें.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

पुनश्चः संकट की इस घड़ी में सही सूचना आपका सबसे बढ़िया हथियार है. हम इंडिया टुडे में स्पष्ट और सटीक सूचना आप तक लाने को प्रतिबद्ध हैं. इस अंक का पीडीएफ संस्करण www.indiatoday.in/emaghindi और www.indiatoday.in/magzterhindi पर मुफ्त उपलब्ध है. हम इस संकट के बारे में अपनी वेबसाइट https://aajtak.intoday.in/indiatoday-hindi/ पर भी अपडेट देते रहते हैं.

Scanned by CamScanner

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

प्रधान संपादक: अरुण पुरी
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
एडिटर: अंशुमान तिवारी
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, शुभम शंखधर
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, युजीत ठाकुर
विशेष संवाददाता: मंजीत ठाकुर, संध्या द्विवेदी
राज्य ब्यूरो: आशीष मिश्र (लखनऊ), अमिताभ श्रीवास्तव (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: रश्मि सक्सेना
चीफ डिजाइनर: असित रॉय
सीनियर डिजाइनर: बालम सिंह रौतेला
डिजाइनर: अमर प्रकाश बिंजोला
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: विक्रम शर्मा, सुबीर हलदर, चंद्रदीप कुमार, शैलेश रावल (अहमदाबाद), मंदार देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
सीनियर फोटो रिसर्चर: शुभोजीत ब्रह्म
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुगला
पब्लिशिंग डायरेक्टर: मनोज शर्मा
एसोसिएट पब्लिशर: अनिल फर्नांडीस
इंपैक्ट टीम: सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु), कौशिकी गांगुली (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
चीफ जनरल मैनेजर: डी.वी.एस. रामाराव
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन बग्गा: (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
रीजनल सेल्स मैनेजर: सैयद आसिफ सलीम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 34; अंक: 25; 30 अप्रैल-6 मई, 2020; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.

- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा के-9, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110 001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां
पश्चिम बंगाल: संकट में भी दबदबे की होड़
पेज 5

भीतर

फुरसत
सवाल+जवाब/जैकलीन फर्नांडीस: कितना मुगालता
पेज 66

आवरण कथा / कृषि

16 उम्मीद की खेती

कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद केंद्र रबी की फसल की कटाई सुरक्षित तरीके से करा लेना चाहती है. क्या खेती इस कहानी का रुख मोड़ सकती है?

बंदीप सिंह

28 उद्योग

फिर शुरू करने की मुश्किलें

उद्योग को दोबारा खोलने की सरकार की योजना का लक्ष्य तो अच्छा था पर जटिल निर्देशों, आपूर्ति शृंखला में उथल-पुथल और मांग में कमी ने सब गड़बड़ कर दिया.

34 धारावी

बम पर बैठा मुंबई

समुद्र किनारे बसे इस शहर की सबसे घनी बस्ती अब कोविड-19 का हॉटस्पॉट है. सामाजिक दूरी न होना धारावी में गंभीर चिंता की वजह क्यों है?

40 कोविड-19 इलाज

अचूक इलाज की तलाश

इस वायरस का टीका तैयार होने में एक साल लग सकता है. भारत और दुनिया को कोविड-19 का सटीक इलाज विकसित करने के लिए वक्त को मात देनी होगी.

45 महामारी की मार

मास्क के पीछे

कोविड-19 के प्रकोप के बाद लॉकडाउन की वजह से इस महामारी के समानांतर कई क्रूर परिणाम उभरकर सामने आए हैं, उन संकटों पर एक नजर.

आवरण फोटो: **संदीप सहदेव**

Scanned by CamScanner

जम्मू-कश्मीरः
वापस पुराने ढर्रे पर!
पेज 8

उत्तराखंडः खिल उठा
पर्यावरण हवा-पानी हुआ शुद्ध
पेज 10

सुर्खियां

समाचार सारः
राज्यपाल की ताकत
पेज 12

अर्थात्:
इक आग का दरिया है...
पेज 13

दिखाने का दम
कोलकाता में 17 अप्रैल को मास्क वितरण के दौरान ममता बनर्जी

एएनआइ

पश्चिम बंगाल लॉकडाउन

संकट में भी दबदबे की होड़

रोमिता दत्ता

पश्चिम बंगाल में कोविड-19 लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार और तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई वाली राज्य सरकार के बीच तू-तू, मैं-मैं 20 अप्रैल बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई. उस दिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से भेजी गई दो अंतर-मंत्रालय टीमें इस बात का जायजा लेने बंगाल पहुंची थीं कि क्या राज्य में लॉकडाउन के नियमों का ठीक से अनुपालन हो रहा है. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस टीम के आने की सूचना टीम के कोलकाता पहुंचने के मात्र एक घंटे पहले दी गई थी, वहीं गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना टीम के पहुंचने के बाद दी. केंद्रीय टीम का इस तरह बंगाल आना राज्य सरकार को रास नहीं आया. राज्य के अधिकारियों ने कथित तौर पर इन टीमों का सहयोग करने से मना कर दिया.

मार्च के आखिर से ही, लॉकडाउन के बाद की स्थितियों को लेकर राज्य और केंद्र के बीच लगातार टकराव दिख रहा है. ममता बनर्जी की सरकार दायरों से बाहर जाकर भी केंद्र के तय गए नियमों की अनदेखी या उल्लंघन करने

Scanned by CamScanner

> **पूरी तरह सुरक्षित** कोलकाता में 11 अप्रैल को राजभवन में भाजपा सांसद दिलीप घोष (भगवा गमछे पहने हुए) और राहुल सिन्हा (ब्लू जैकेट में)

को आमादा दिखती है, तो नरेंद्र मोदी सरकार भी गृह मंत्रालय के जरिए उसे लगातार धमकी भरे आदेश जारी कर रही है. इसकी मूल वजह राज्य में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए भाजपा और टीएमसी के बीच प्रतिद्वंद्विता है. 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा टीएमसी के खिलाफ प्रमुख दावेदार है, और अगर 2019 के लोकसभा नतीजों को संकेत मानें तो दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है. दोनों में कोई भी दल कमजोर दिखने का जोखिम नहीं उठा सकता और न ही दूसरे को हावी दे सकता है. चिंता यह है कि इस महामारी के समय यह खींचतान राज्य के लिए ठीक नहीं है.

टकराव के मुद्दे

लॉकडाउन को लेकर दोनों पक्षों के बीच 'असहमति' और टकराव की शुरुआत मार्च के अंत से ही होने लगी थी. 25 मार्च को मोदी सरकार के देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से ही लोगों को अपना सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन संकट में घिरा नजर आ रहा है. कोई घर से बाहर तभी निकल सकता है जब उसके पास राशन या दवाएं खरीदने जैसे आधिकारिक तौर पर अनुमोदित कारण हों. धार्मिक समारोहों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, और गैर-जरूरी सामान जैसे मिठाइयां बेचने वाले स्टोर बंद कर दिए गए थे. वैसे, इस केंद्रीय आदेश का अनुपालन कराना स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी थी.

विपक्ष ने पश्चिम बंगाल सरकार पर इस आदेश के अनुपालन में रुचि नहीं लेने का आरोप लगाया. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केंद्र की अधिसूचना आने के बावजूद—और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्देश है—ममता बनर्जी की सरकार पर इसे गंभीरता से न लेने और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने के आरोप लगाए गए. इसके लिए मिठाई दुकानों को लेकर फैसले का हवाला दिया गया. राज्य सरकार ने 30 मार्च को मिठाई की दुकानों को 'बंगालियों के लिए आवश्यक वस्तु' बताया और मिठाई की दुकानों को दोपहर से 4 बजे के बीच खोलने की अनुमति दे दी. हालांकि अन्य राज्यों में उन्हें बंद रखा गया है और केंद्र की आवश्यक वस्तुओं की सूची में यह नहीं है.

ममता सरकार पर एक और आरोप सामाजिक दूरी के मानदंडों और धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देशों को पूरा नहीं करने का लगा. 10 अप्रैल को, राज्य पुलिस को कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार की नमाज के लिए एक मस्जिद में इकट्ठा हुई सैकड़ों लोगों की भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा. भाजपा सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसके बारे में ट्वीट करते हुए लिखा, ''जब मुख्यमंत्री फूल और पान की दुकानें और मिठाई की दुकानें खोलने जैसे लापरवाही भरे आदेश देंगी तो लोग कैसे गंभीर होंगे. फिर तो यही सब होना है...'' उसी दिन केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष आइएएस/आइपीएस अफसरों को पत्र लिखकर याद दिलाया कि बिना किसी अपवाद के किसी भी तरह के धार्मिक जुटान की अनुमति नहीं है.

अगले दिन, 11 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और पत्र भेजा, जिसमें लिखा था: ''सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने की सूचना है.'' पत्र में यह भी कहा गया कि विशेष रूप से राजाबाजार, नारकेल डांगा, तोपसिया, मटियाबुर्ज, गार्डन रीच, इकबालपुर और कोलकाता के मानिकतल्ला जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में सब्जी, मछली और मांस के बाजारों में सामाजिक-सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया जा रहा था. वहीं, बनर्जी ने केंद्र पर मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस कोई सांप्रदायिक वायरस नहीं है, यह एक मानव रोग है.'' उन्होंने पत्रकारों को बताया, ''लॉकडाउन, मानवीय भावनाओं के साथ जारी रहेगा, बाजार खुले रहेंगे और आवश्यक बिक्री वाली दुकानें खुली रहेंगी.'' वैसे जरूरी वस्तुओं के बाजार जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों की अनदेखी को लेकर बनर्जी की आलोचना हुई और इस अनदेखी से यह 'मानवीय बीमारी' भारी पड़ सकती है क्योंकि रोग समुदाय की परवाह किए बिना फैलता है. दो दिन बाद, 13 अप्रैल को, गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार को लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए एक और पत्र भेजा.

10 अप्रैल को भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता ने लिखा कि कोरोना के आंकड़े छुपाना बहुत भारी पड़ सकता है

गृह मंत्रालय ने 11 अप्रैल को एक और पत्र लिखकर एक अन्य मुद्दा उठाया और शायद बनर्जी इसी वजह से ज्यादा आक्रामक हो गईं. पत्र में लिखा था, ''ऐसी सूचना मिली है कि मुफ्त राशन का वितरण संस्थागत वितरण प्रणाली के जरिए न होकर सियासी नेताओं के जरिए किया जा रहा है. हो सकता है कि इससे कोविड-19 संक्रमण फैल गया हो.'' हालांकि रिपोर्ट कही सुनी बातों पर आधारित या पक्षपातपूर्ण भी हो सकती है क्योंकि ऐसे ज्यादातर आरोप भाजपा के कई सांसदों ने लगाए थे. आरोप यह है कि टीएमसी नेता आधिकारिक राशन-वितरण प्रणाली को दरकिनार करते हुए विभाग के संसाधनों को 'हथियाकर' खुद अनाज बांट रहे हैं. यह सच है या नहीं पर 17 अप्रैल को, बनर्जी की सरकार ने राशन वितरण का कार्य देख रहे राज्य के वरिष्ठ नौकशाह और खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव मनोज अग्रवाल को बदलने का आदेश दिया. बनर्जी ने इस तबादले को इस तरह समझाया: ''हम एक नए सचिव की नियुक्ति कर रहे हैं क्योंकि बार-बार निर्देशों के बावजूद 10 फीसद लाभार्थियों को उनके मासिक आवंटन का आधा भी नहीं दिया जा सका है.'' राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी इस मुद्दे को लेकर कई बार ट्वीट किए. 18 अप्रैल को, अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा: ''पीडीएस घोटाला दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है. पीडीएस प्रणाली एक तरह से राजनैतिक अपहरण का शिकार हो चुकी है जो कि एक अपराध है. मुफ्त राशन जरूरतमंदों के

Scanned by CamScanner